दिनांक : 14 फरवरी 2014

आंध्र प्रदेश में तालमेल की जरुरत

– अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

जैसे जैसे यूपीए का कार्यकाल समाप्त होने के नजदीक है, व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी कम होती जा रही है। "मेरे बाद प्रलय" यही यूपीए अपने बाद छोड़कर जाना चाहती है। उसके कार्यकाल के शुरुआती दिन संस्थानों के पतन, अर्थव्यवस्था के विकास की गति में ढिलाई, भ्रष्टाचार और सरकार के फैसले लेने की विश्वसनीयता के स्तर के कम होने के रहे।

तेलंगाना राज्य के गठन के संबंध में विवादास्पद प्रस्ताव पर यूपीए अब पूरी तरह हिम्मत हार चुकी है। उसकी अपनी ही पार्टी के अंदर ऐसे तत्व पैदा हो गए हैं जिन पर वह नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है। बिना किसी शोर शराबे और हंगामे के संसद का सत्र चलना अब दुर्लभ हो चुका है। संसद की कार्यवाही में बाधा प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा नहीं पहुंचाई जा रही है बल्कि यूपीए के अपने सदस्य ही इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय पूरी तरह ठप्प हो चुका है और जो मुददे हाथ में हैं उन्हें सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है।

बड़े पैमाने पर आम सहमति कायम करने की दिशा में काम करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। सीमान्ध्र की राजधानी, सीमान्ध्र में अलग उच्च न्यायालय के गठन करने जैसे मुददे दो राज्य बनने के कारण इस क्षेत्र को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के संबंध में हैं, क्षेत्र में पानी और बिजली के संबंध में अन्य मुददों का भी समाधान किया जाना है। एनडीए ने झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन करने समय सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया। गुरुवार को संसद में गतिरोध और शर्मनाक स्थिति पैदा करने के लिए यूपीए ही जिम्मेदार है। सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वाले अधिकतर सांसद यूपीए के थे। तेलंगाना और सीमान्ध्र के प्रतिनिधियों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। सरकार ने तालमेल कायम करने के लिए कोई मंच प्रदान नहीं किया। संसद दोनों क्षेत्रों की आकांक्षाओं पर विचार–विमर्श करने में असमर्थ रही। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय लोकतंत्र की बदनामी हुई। संसद में जो कुछ होता है उससे राजनीतिज्ञों की छवि पर असर पड़ता है। तेलंगाना और सीमान्ध्र दोनों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। यूपीए सरकार हर तरह की शासन कला छोड़ दी है। अभी भी देर नहीं हुई है कि मेल मिलाप के लिए संसद के भीतर और बाहर एक मंच प्रदान किया जाए ताकि तेलंगाना का गठन हो सके। साथ ही सीमान्ध्र के लोगों की जायज चिंताओं को भी दूर किया जाए।

*****